(f) the quantum of water received and recorded in the water meter of the IDBI Quarters at Ghatkopar, Bombay in each Bill since the last 10 years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) and (b) The Industrial Development Bank of India (IDBI) has reported that it got the additional 1.5 Diameter water connection for its staff quarters at Ghatkopar in the year 1991 and the existing water lines were cleaned in December, 1994.

(c) No, Sir.

(d) and (e) IDBI has reported that it brought to the notice of Bombay Municipal Corporation the position of inadequate water supply on 22-11-90 and again on 23-3-1992.

(f) IDBI has reported that based on available records of the last about 2 years, on an average the quantum of water received was around 3,405 thousand litres per month.

देशी और विदेशी ऋण पर दिया गया ब्याज

2271. **श्री राघवजी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार को देशी और विदेशी ऋण पर पृथक-पृथक वर्षवार कितना-कितना ब्याज चुकाना पड़ा;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान वर्षवार ऐसी ब्याज की कितनी राशि चुकायी जानी थी, लेकिन चुकाई नहीं जा सकी, तथा इसे समय पर अदा न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ऐसे ऋणों पर ब्याज के भुगतान खर्च को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा आंतरिक और विदेशी ऋण पर चुकाए गए वर्ष-वार ब्याज की धनराशि निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपए)

	1991-92	1992-93	1993-94 (अनन्तिम)
आन्तरिक ऋण	11317	13542	15587
विदेशी ऋण	2704	3529	3724
जोड़:	14021	17071	19311

(ख) सभी दायित्व समय पर पूरे किए गए।

(ग) सरकार का राजकोषीय घाटे को वर्ष 1994-95 (संशोधित अनुमान) के सकल घरेलू उत्पाद के 6.7 प्रतिशत से घटाकर 1995-96 (बजट अनुमान) में सकल घरेलू उत्पाद का 5.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। राजकोषीय घाटे में कमी की प्रक्रिया को जारी रखने का प्रस्ताव है। राजकोषीय घाटे में कमी होने से ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात धीरे-धीरे स्थिर हो जाएगा और अन्ततः घट जाएगा।

मध्य प्रदेश में आयकर कार्यालय

2272. **श्री राघवजी:** क्या वित्त मंत्री की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में ऐसे कौन-कौन से शहर हैं जहां आयकर कार्यालय के अपने निजी भवन नहीं हैं।

(ख) इन स्थानों में उनके अपने भवनों का निर्माण करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) उपरोक्त स्थानों में से कितने स्थानों पर मार्च, 1996 तक उसके अपने कार्यालय भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) मध्य प्रदेश में निम्नलिखित 20 आयकर कार्यालयों के पास इस समय अपने कार्यालय भवन नहीं हैं:-

विदिशा, शिवनी, रीवा, राजनन्दगांव, राजगढ़, खरगोन, कटनी, जगदलपुर, धार, दमोह, छिन्दवाड़ा, अंतरपुर, बालाघाट, शिवपुरी, मन्दसौर, भिलाई, सागर, खंडवा, धामतरी, बिलासपुर।

(ख) और (ग): दो स्टेशनों के संबंध में अपने कार्यालय भवनों का निर्माण पहले ही चल रहा है। आठ स्टेशनों के संबंध में उचित भूखंड पहले ही खरीदे जा चुके है और इन स्टेशनों पर मार्च, 1996 तक कार्यालय भवनों के निर्माण की कार्यवाही शुरू होने की आशा है। बकाया 10 स्टेशनों के मामले में उचित भूखण्डों के आवंटन के राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है।

'Funding Activities of SCICI'

2273. SHRI S. AUSTIN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the SCICI has not adopted any cohesive plan for funding activities;

(b) whether it is a fact that SCICI funds to various sectors without adequate specialization; and